संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

29th July, 2024

DO No. 31/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleagues,

As is expected from ardent tax administrators, I am sure all my CBIC brethren would have closely followed the Union Budget. This is the time when a lot of discussion happens on the changes and we should be aware of the contours of the Budget to dispel any confusions or doubts in the mind of taxpayers. The overarching goal for indirect taxes is clear – to create a simplified, efficient tax system that supports India's growth and development aspirations. Hon'ble FM has announced that a comprehensive review of the rate structure will be undertaken over the next six months to rationalise and simplify the structure for ease of trade, removal of duty inversion and reduction of disputes. Additionally, there will be a concerted effort to deepen digitalization, particularly within Customs.

I am happy to inform that the DPC for JTS regularisation for the vacancy Year 2013-14 was conducted in UPSC today. The Board is keen that the regularisation exercise be completed for subsequent years at the earliest. Therefore, requisite documents have been sought from the field formations. It is an earnest request to urgently comply with the timelines set by the Board in this regard. The Board endeavours to carry out only regular promotions in the future.

Based on intelligence gathered by SIIB Mundra, one export consignment of a merchant exporter with declared description as *Diclofenac Tab* and *Gebedol Tab* was intercepted and examined. While the declared item was found in the front end of the container, examination revealed boxes containing undeclared medicine strips bearing marking as 'Tramaking 225' with the composition *Tramadol Hydrochloride*. Neither the strips nor the boxes had any details of the manufacturer. Tramadol is notified as a psychotropic substance under the NDPS Act and has gained notoriety

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

in recent times for its abuse as a synthetic opioid drug. In a follow up action against the same exporter, another consignment was seized and an abandoned warehouse in Ahmedabad was located with more quantities of Tramadol. Overall, so far, the seizures are to the tune of 68,00,000 tablets of Tramadol with a street value of about Rs. 110 Crores in the grey market. Excellent detection by the officers of Mundra Customs!

Fighting against the menace of fake ITC, the officers of CGST Vadodara-I Commissionerate, utilized data analytics to uncover a fake invoicing racket. The investigation against three suspect firms revealed that they had availed and passed fake input tax credit to the extent of Rs. 169.58 crores on the strength of invoices received from non-existent entity without actual receipt of goods. Kudos to the team for unearthing the fraud!

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

29 जुलाई, 2024

DO No. 31/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

जैसा कि उत्साही कर प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है, मुझे यकीन है कि मेरे सभी सीबीआईसी के अधिकारीगणों ने केंद्रीय बजट को बारीकी से अध्ययन किया होगा। यह वह समय है जब बदलावों पर काफी चर्चा होती है और हमें करदाताओं के मन में किसी भी भ्रम या संदेह को दूर करने के लिए बजट की रूपरेखा से अवगत होना चाहिए। अप्रत्यक्ष करों का व्यापक लक्ष्य स्पष्ट है - एक सरलीकृत, कुशल कर प्रणाली बनाना जो भारत की वृद्धि और विकास आकांक्षाओं का समर्थन करती हो। माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि व्यापार में सुगमता, ड्यूटी इन्वर्शन को हटाने और मतभेदों को कम करने के लिए संरचना को सरल बनाने के लिए अगले छह महीनों में दर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से सीमा शुल्क के अंतर्गत डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाएगा।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वैकेंसी ईयर 2013-14 के लिए जेटीएस नियमितीकरण के लिए डीपीसी आज यूपीएससी में आयोजित की गई थी। बोर्ड चाहता है कि आगामी वर्षों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसलिए, क्षेत्रीय संरचनाओं से अपेक्षित दस्तावेज मांगे गए हैं। इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा का तत्काल अनुपालन करने का अनुरोध है। बोर्ड भविष्य में केवल नियमित पदोन्नति करने का प्रयास करता है।

एसआईआईबी (SIIB) मुंद्रा द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के आधार पर, *Diclofenac Tab and Gebedol Tab* के रूप में घोषित विवरण के साथ एक मर्चेंट एक्सपोर्टर की एक एक्सपोर्ट कन्साइनमेंट को रोका गया और उसकी जांच की गई। जबकि कंटेनर के सामने वाले हिस्से में घोषित वस्तु पाई गई थी, जांच में अघोषित दवा स्ट्रिप्स के बक्से पाए गए, जिन पर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के संयोजन के साथ 'ट्रामेकिंग 225' अंकित था। निर्माता का न तो स्ट्रिप्स और न ही बक्सों पर कोई विवरण था। ट्रामाडोल को एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक साइकोट्रॉपिक पदार्थ के रूप में अधिसूचित किया गया है और सिंथेटिक opioid ड्रग्स

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

के रूप में इसके दुरुपयोग के लिए हाल के दिनों में इसने कुख्याति प्राप्त की है। उसी निर्यातक के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई में, एक और खेप जब्त की गई और अहमदाबाद में एक पुराने गोदाम में अधिक मात्रा में ट्रामाडोल पाया गया। कुल मिलाकर, अब तक, ट्रामाडोल की 68,00,000 गोलियों की जब्ती हुई है, जिनकी कीमत ग्रे मार्केट में लगभग 110 करोड़ रुपये है । मुंद्रा सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य!

नकली आईटीसी के खतरे के खिलाफ लड़ते हुए, सीजीएसटी वडोदरा-I कमिश्नरेट के अधिकारियों ने फर्जी इन्वॉइसिंग रैकेट को उजागर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया। तीन संदिग्ध फर्मों के खिलाफ जांच से पता चला कि उन्होंने माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना गैर-मौजूद इकाई से प्राप्त इनवॉइस रैकेट के बल पर 169.58 करोड़ रुपये के लगभग फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और पारित किया। फर्जी इन्वॉइसिंग रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए टीम को बधाई!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।